KANPUR PLASTIPACK LTD
CIN: L25209UP1971PLC003444

TEL: +91 (0512) 2691 113-6
+91 (0512) 2256 813
FAX: +91(0512) 2691117
Email: info@kanplas.com
Web: www.kanplas.com

REGD OFFICE & WORKS
D-19-20, PANKI IND.AREA,
P.O.UDYOG NAGAR
KANPUR – 208 022
INDIA

22nd September, 2017

The Department of Corporate Services
The Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
MUMBAI-400 001

Dear Sir,

Scrip Code : 507779

Sub.: Submission of newspaper notice for the filing of Draft Letter of Offer to SEBI.

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement (corrigendum) published on 21/09/2017.

Kindly take this on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For **KANPUR PLASTIPACK LTD.**

(Ankur Srivastava)
Company Secretary

Encl: A/a

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT

(This is a public announcement for information purposes only and is not an offer document)

KANPUR PLASTIPACK LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Kanpur Plastipack Private Limited', a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 pursuant to the grant of Certificate of Incorporation dated July 26, 1971 by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. Subsequently, our Company was converted into public limited company and a fresh Certificate of Incorporation in the name of 'Kanpur Plastipack Limited' was issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur on December 9, 1985. For further details, please refer the chapter titled *"History and Corporate Structure"* beginning on page 64 of the Draft Letter of Offer.

Registered Office: D 19-20, Panki Industrial Area, P. O. Udyog Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh, India – 208022
Telephone: +91-512-2691113/14/15/16 **Facsimile:** +91-512-2691117
Contact Person: Mr. Ankur Srivastava, Company Secretary and Compliance Officer
Email: secretary@kanplas.com; **Website:** www.kanplas.com; **Corporate Identity Number:** L25209UP1971PLC003444

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. MAHESH SWARUP AGARWAL, MR. MANOJ AGARWAL AND MR. SHASHANK AGARWAL

ISSUE OF [•] EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 2,000 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [•] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [•] FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [•] ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED *"TERMS OF THE ISSUE"* BEGINNING ON PAGE 122 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This corrigendum to the public announcement should be read in conjunction with the public announcement dated September 18, 2017 published on September 19, 2017 in the following newspapers: Business Standard – (English) National daily – All Editions, Business Standard (Hindi) National Daily - All Editions and Lok Bharti – (Hindi) (Regional Language) (**"Public Announcement"**) to inform the public that our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares to eligible equity shareholders on rights basis. The eligible equity shareholders should note the following amendment to the Public Announcement -

1. The date of filing of Draft Letter of Offer (**"DLOF"**) with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) and BSE Limited should be read as **September 18, 2017** instead of September 18, 2015.

Note: Capitalised terms used but not defined here shall have the same meaning as under the DLOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

VIVRO

Vivro Financial Services Private Limited
607-608 Marathon Icon, Veer Santaji Lane, Opposite Peninsula Corporate Park,
Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, India – 400013
Telephone Number: +91-22-66668040; **Facsimile Number:** +91-22-66668047
Website: www.vivro.net; **Email:** kanplas@vivro.net
Investor Grievance Email: investors@vivro.net
Contact Person: Mr. Anish Akruwala / Mr. Harish Patel
SEBI Registration Number: INM000010122
CIN: U67120GJ1996PTC029182

For and on behalf of
KANPUR PLASTIPACK LIMITED
Sd/-
Mr. Ankur Srivastava
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kanpur
Date: September 21, 2017

This corrigendum to the public announcement should be read with Public Announcement and will be available on the website of designated stock exchange i.e. BSE Limited at (www.bseindia.com), website of our Company (www.kanplas.com) and website of the Lead Manager to the Issue i.e. Vivro Financial Services Private Limited (www.vivro.net).

Raka

संक्षेप में

बीएस-1 और बीएस-2 पर रुख साफ करें राज्य

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को देश के पांच उत्तरी राज्यों से भारत स्टेज-1 और भारत स्टेज-2 वाहनों के चलने और उनके पंजीकरण पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। दरअसल ये वाहन दिल्ली – एनसीआर में प्रतिबंधित हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के अध्यक्षता वाले एक पीठ ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों से शुक्रवार तक स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि क्या वे अपने इलाकों में इन वाहनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। *भाषा*

कमल हासन से चेन्नई में मिले केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अभिनेता कमल हासन से चेन्नई मुलाकात की जिनके राजनीति में आने को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। *भाषा*

कॉफी डे के कार्यालयों पर छापे

रघु कृष्णन
बेंगलुरु, 21 सितंबर

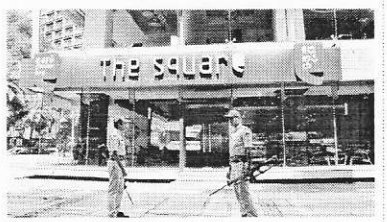
आयकर विभाग ने भारत की सबसे बड़ी कॉफी शृंखला कॉफी डे इंटरप्राइजेज और इसके प्रमोटर वीजी सिद्धार्थ के 25 से ज्यादा कार्यालयों व बागानों में आज तलाशी ली। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह नियमित तलाशी है, जो बेहिसाबी धन की जांच के लिए होती है।

भारत में 1988 में पहला साइबर कैफे खोलने और ब्रांड की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ देश के प्रमुख कॉफी निर्यातकों में से एक हैं। टेक्नोलॉजी फर्म में निवेशक के रूप में उन्होंने आईटी सेवा फर्म माइंडट्री में भी निवेश किया और वह कुछ ऐसे लोगों में शुमार हैं, जिन्होंने इन्फोसिस की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को 100 फीसदी बोली नहीं मिलने पर उसे संकट से उबरने में मदद पहुंचाई थी।

सिद्धार्थ कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद हैं। कृष्णा ने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कृष्णा की मदद की और कांग्रेस पार्टी को 1999 विधानसभा चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई।

आयकर विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी अभियान आज सुबह शुरू हुआ, जो नियमित जांच की कवायद थी। यह तलाशी केपनी के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय, उसके मुंबई और चेन्नई कार्यालय और चिकमंगलूर के बागान में हुई, जो कर्नाटक का कॉफी उत्पादक इलाका है।

सबसे बड़ी संगठित कॉफी रिटेल चेन के अलावा कॉफी डे समूह टेक्नोलॉजी पार्क और सेज के हार्डवेयर ग्लोबल आईटी फर्म, सिकल, एक एकीकृत लॉजिस्टिक फर्म और कॉफी डे ट्रेडिंग का संचालन करता है, जो केपनियों को निवेश में मदद करती है। साथ ही इस समूह का सेराई



कर्नाटक में 3 लक्जरी रिसॉर्ट का परिचालन करता है।

छापेमारी की खबरों के बाद गुरुवार को कॉफी डे के शेयर के दाम 10 प्रतिशत से ज्यादा नीचे चले गए, जो अंत में 3.35 प्रतिशत गिरकर 233.80 रुपये पर बंद हुआ। निवेशकों ने सिकल लॉजिस्टिक्स से भी किनारा किया, जो आखिर में बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 3.65 प्रतिशत गिरकर 217.80 रुपये पर बंद हुआ।

बेंगलूरु: पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के दामाद सिद्धार्थ का कॉर्पोरेट कार्यालय भवन, जहां गुरुवार को आयकर अधिकारियों ने तलाशी ली। आयकर अधिकारियों ने कैफे कॉफी डे के संस्थापक के मुंबई, चिकमंगलूर और चेन्नई स्थित कई कार्यालयों में तलाशी ली *फोटो-पीटीआई*

घटती विकास दर से बढ़ रही फिकर

पृष्ठ 1 का शेष

चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय करने की बात कही है। यह 2016-17 के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक और संशोधित अनुमान 2.80 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि अब तक के उपलब्ध राजकोषीय घाटे के आंकड़े बताते हैं कि व्यय और राजस्व में अंतर 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जो पूरे वित्त वर्ष के 5.46 लाख करोड़ रुपये का करीब 92 प्रतिशत है। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद केंपनियां द्वारा अपने स्टॉक खाली करने और नया स्टॉक फिलहाल नहीं बनाने से अप्रैल-जून तिमाही में आर्थिक विकास दर कम होकर 5.7 प्रतिशत रह गई। नतीजा यह हुआ कि भारत लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी में तेजी के लिहाज से पिछड़ गया। दोनों तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2016-17 को अप्रैल-जून तिमाही में 7.9 प्रतिशत के मुकाबले जीडीपी विकास दर कम है।

अप्रैल-जून में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर भी कम होकर 1.2 प्रतिशत रह गई, जो जनवरी-मार्च में 5.3 प्रतिशत थी। खनन और संबंधित गतिविधियों में भी आलोच्य अवधि के दौरान 0.7 प्रतिशत की कमी आई। कृषि विकास दर पिछले तिमाही की 5.2 प्रतिशत और अक्टूबर-दिसंबर 2016-17 की 6.9 प्रतिशत के मुकाबले कम होकर 2.3 प्रतिशत रह गई।

CORRIGENDUM TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT
(This is a public announcement for information purposes only and is not an offer document)

KANPUR PLASTIPACK LTD

KANPUR PLASTIPACK LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Kanpur Plastipack Private Limited', a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 pursuant to the grant of Certificate of Incorporation dated July 26, 1971 by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. Subsequently, our Company was converted into public limited company and a fresh Certificate of Incorporation in the name of 'Kanpur Plastipack Limited' was issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur on December 9, 1985. For further details, please refer the chapter titled *"History and Corporate Structure"* beginning on page 64 of the Draft Letter of Offer.

Registered Office: D 19-20, Panki Industrial Area, P. O. Udyog Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh, India - 208022
Telephone: +91 - 512-2691113 / 14 / 15 / 16 **Facsimile:** +91 - 512 - 2691117
Contact Person: Mr. Ankur Srivastava, Company Secretary and Compliance Officer
Email: secretary@kanplas.com; **Website:** www.kanplas.com; **Corporate Identity Number:** L25209UP1971PLC003444

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. MAHESH SWARUP AGARWAL, MR. MANOJ AGARWAL AND MR. SHASHANK AGARWAL

ISSUE OF [●] EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 2 000 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF [●] RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [●] FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON [●] ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED *"TERMS OF THE ISSUE"* BEGINNING ON PAGE 122 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER.

This corrigendum to the public announcement should be read in conjunction with the public announcement dated September 18, 2017 published on September 19, 2017 in the following newspapers: Business Standard - (English) National daily - All Editions, Business Standard (Hindi) National Daily - All Editions and Lok Bharti - (Hindi) (Regional Language) (**"Public Announcement"**) to inform the public that our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares to eligible equity shareholders on rights basis. The eligible equity shareholders should note the following amendment to the Public Announcement -

1. The date of filing of Draft Letter of Offer ("**DLOF**") with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and BSE Limited should be read as **September 18, 2017** instead of September 18, 2015.

Note: Capitalised terms used but not defined here shall have the same meaning as under the DLOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

VIVRO

Vivro Financial Services Private Limited
607-608 Marathon Icon, Veer Santaji Lane, Opposite Peninsula Corporate Park, Off Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, India – 400013
Telephone Number: +91-22-66668040; **Facsimile Number:** +91-22-66668047
Website: www.vivro.net; **Email:** kanplas@vivro.net
Investor Grievance Email: investors@vivro.net.
Contact Person: Mr. Anish Akruwala / Mr. Harish Patel
SEBI Registration Number: INM0000010122
CIN: U67120GJ1996PTC029182

For and on behalf of
KANPUR PLASTIPACK LIMITED
Sd/-
Mr. Ankur Srivastava
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kanpur
Date: September 21, 2017

This corrigendum to the public announcement should be read with Public Announcement and will be available on the website of designated stock exchange i.e. BSE Limited at (www.bseindia.com), website of our Company (www.kanplas.com) and website of the Lead Manager to the Issue i.e. Vivro Financial Services Private Limited (www.vivro.net). Rajat

GITANJALI
TRUST FOREVER

PUBLIC NOTICE

The Public at large, my valued customers and those associated with Gitanjali Group of Companies are hereby cautioned and informed that certain unscrupulous entities including a handful of franchisees have, with ulterior motive and mala fide intent, banded together to malign the Company's image and show me in poor light. They are campaigning against me and the Company in various media like Newspapers, Television, the Internet and even staging illegal public protests & demonstrations. The articles that are being published and extensively circulated in various media above, inter-alia, are casting aspersions against me and the Company with a view **to create a false picture in the eyes of the public** that the Company is fraudulent and is, allegedly, engaged in defrauding people.

Being concerned with such illegal and preposterous allegations and considering the probable misunderstandings that these may create, I take it as my duty to convey and clarify by this public notice that all such campaigning and mischief/mongering are initiated by a few miscreants **and all their allegations are false, misleading and with mala fide intent and to camouflage their own misdeeds.** Their aim is to use these illegal means and extort money by creating false public records so that the Company would agree to their illegal demands. The Public may please note that:

- These are a few ex-franchisees of the Company with whom the Company has commercial disputes and ongoing litigations *namely Digvijaysinh Jadeja (Divyanirman Jewels), Rajat & Pranshu Gupta (Tara Jewels), S.V.Hariprasad (Mevа Jewels), R K Shukla (Anu Creations), Vaibhav Malvi (Vaibhav Jewellers)* etc.
- The Company has already filed Complaints with the Police/Economic Offenses Wing and has also initiated appropriate legal proceedings against these franchisees to recover Crores of Rupees and jewellery stock belonging to the Company, which these franchisees have defaulted to pay or have illegally retained.
- **Digvijaysinh Jadeja** (named above) has himself been convicted of abetting the suicide of an entire family in Gujarat, and sentenced to 10 years rigorous imprisonment and is currently on bail. The Hon'ble Gujarat High Court has also quashed his false and frivolous police complaint against me. As a matter of fact, the Company has filed a Recovery Suit for over Rs. 70 Crores against him way back in August 2014, which is pending for final hearing.
- **Rajat Gupta of Tara Jewels** has failed to return the Company's stock worth almost Rs. 3 Crores and yet recently has got published extremely illegal and **defamatory** public notice displaying my picture attempting to portray that I am declared as a 'Proclaimed Offender' by a court in Chandigarh in a Cheque bouncing matter, notwithstanding the fact that **I am neither a signatory of the Cheque nor an accused in the pending complaint.** The Cheques were issued against return of Company's stock, which Rajat Gupta & his firm has illegally retained and despite this, proceeded to illegally-encash the Cheques. The mala fide intent is absolutely clear in this case.
- **R K Shukla,** of Anu Creations, Orissa, illegally retained and encashed a demand draft of Rs.50 Lacs which the Company had given to him against return of over Rs.3 Crores of Company's jewellery held by him. However, Mr. Shukla took the DD but did not return the stock obviously with mala fide intent. The Company has filed a complaint against him in the EOW, Mumbai and also initiated arbitration against him/his firm and recently the hon'ble Bombay High Court passed an ad-interim injunction against him not to use the Rs.50 Lacs till the goods are returned and has also appointed a Court Receiver in the matter.
- However, the matters are sub-judice and are pending adjudication by the competent courts and/or tribunals whose final decisions we will respect.
- Making such public allegations when the matters are sub judice therefore is blatantly illegal and tantamount to defamation and contempt of court, for which the Company is initiating strict legal action against these defractors.
- It is all the more clear and obvious that these entities do not have any merits on their side and as such are resorting to such illegal gimmicks only to extract wrongful gains.

There is therefore no reason to panic or be concerned on account of such illegal campaigns and I request you to kindly ignore any communication or notices that these vested interests put up against the Gitanjali Group or me. The reputation and image of our brand has been built painstakingly over the years and I hope that you will not let such baseless allegations and illegal actions cloud your judgement or mind.

I am certain that such allegations against the Gitanjali Group and me will not stand the scrutiny of law and will meet with its logical end in our favor. I therefore request you to disregard and ignore such illegal campaigning as above and continue your trust and confidence with the Gitanjali Group and me.

At the same time I assure all of you that the Company will do all that is required to maintain the goodwill and reputation that the Company has built over so many years of effort and expense.

For GITANJALI GROUP OF COMPANIES

(Mehul Choksi)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

GITANJALI
TRUST FOREVER

पेट्रोलियम पर जीएसटी को लेकर डर रहे राज्य

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 21 सितंबर

राज्य सरकारें पेट्रोलियम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने की इच्छुक नहीं हैं। नए अप्रत्यक्ष कर से होने वाले राजस्व नुकसान पर पहले 5 साल तक राज्यों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है, लेकिन उन्हें डर है कि पेट्रोलियम पर जीएसटी लागू होने से वे लचीलापन गंवा देंगे, जबकि पेट्रोलियम पर कर राज्यों की आमदनी का प्रमुख स्रोत है।

पांच पेट्रोलियम उत्पाद– कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन (एटीएफ) जीएसटी के दायरे से अभी बाहर हैं। जीसटी परिषद ने इन्हें नए कर के दायरे में लाने पर चर्चा नहीं की है, हालांकि परिषद इस पर 2 साल में फैसला कर सकती है।

पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क में कटौती ने करने की वजह से केंद्र की आलोचना हो रही है वहीं राज्यों को पेट्रोलियम के दाम में बढ़ोतरी से ज्यादा लाभ हो रहा है। राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मूल्यवर्धित कर या बिक्री कर पेट्रोलियम के दाम के मुताबिक लगता है, जबकि केंद्र सरकार विशेष शुल्क लगाती है। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र ने वैट और विशेष शुल्क दोनों लगाया है।

जेपी मॉर्गन की ओर से आयोजित निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'जहां तक जीएसटी के दायरे में और माल शामिल किए जाने का सवाल है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को इसके दायरे में लाया जाना ज्यादा आसान है।' पेट्रोलियम के अलावा रियल एस्टेट, बिजली और शराब इसके दायरे से बाहर हैं।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार, केंद्र व राज्यों को जीएसटी के मसले पर मध्यस्थ रह चुके हैं, ने कहा कि राज्यों का तर्क था कि उन्हें भरोसा नहीं है कि पेट्रोलियम पर जीएसटी का संग्रह किस तरह से व्यवहार करेगा, इसलिए वे चाहते हैं कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से इसे बाहर रखा जाए।

मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकारें वैट राजस्व का 50-55 प्रतिशत पेट्रोलियम से पाती हैं और ऐसे में वे इस पर संप्रभुता खोना नहीं चाहतीं।

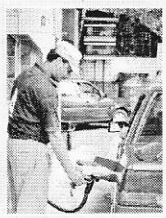
डेलॉयट के एमएस मणि ने कहा, 'राज्यों के वैट में पेट्रोलियम की बड़ी हिस्सेदारी होती है और इसलिए वे इसे जीएसटी के तहत लाए जाने को लेकर अनिच्छुक हैं।'

लेकिन अगर जीएसटी के कारण राजस्व का नुकसान होता है तो राज्यों को पूर्ण मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है, इसके बारे में मणि ने कहा कि राज्यों को अलग अलग दरों को लेकर लचीलापन मिलती है और जीएसटी से देश भर में एक दर हो जाएगी, जिसका असर राज्यों के ऊपर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, 'ऐतिहासिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट दरों में भारी अंतर रहा है और कुछ राज्य मूल्यानुसार दर के अलावा विशेष कर लगाते रहे हैं।' उदाहरण के लिए कर्नाटक में पेट्रोल पर 30 प्रतिशत और डीजल पर 19 प्रतिशत बिक्री कर लगता है, वहीं पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पर 25 प्रतिशत और डीजल पर 17 प्रतिशत कर है। महाराष्ट्र में वैट और विशेष शुल्क पेट्रोल पर 26 प्रतिशत और 11 रुपये प्रति लीटर और कुछ इलाकों में 25 प्रतिशत और 11 रुपये प्रति लीटर है।

खेतान ऐंड कंपनी के अधिषेक रस्तोगी का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाना शुरुआत से ही विवाद का विषय रहा है।

पेट्रोलियम पर जीएसटी की मुश्किलें



- भले ही घाटे पर 5 साल तक मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन अपने कराधान के अधिकार को लेकर लचीलापन चाहते हैं राज्य
- पेट्रोलियम पर केंद्र सरकार विशेष कर लगाती है, जबकि राज्य मूल्यानुसार कर लगाते हैं
- कीमतें बढ़ने से राज्यों को होता है ज्यादा लाभ

अगस्त के लिए 30 लाख जीएसटी रिटर्न, जुलाई से कम

इंदिवजल धस्माना और भाषा
नई दिल्ली, 21 सितंबर

अगस्त महीने में करीब 29.7 लाख करदाताओं ने इनपुर-आउटपुट रिटर्न जीएसटीआर 3बी का सारांश दाखिल किया है, जो जुलाई महीने में दाखिल 46 लाख जीएसटीआर 3बी की तुलना में बहुत कम है। रिटर्न दाखिल करने वाले करीब 46 प्रतिशत लोगों ने 20 सितंबर को रिटर्न दाखिल किया, जो इसके लिए अंतिम तिथि थी। इसकी वजह से आखिरी दिन होने वाली भीड़ के कारण समस्याएं भी आईं।

बहरहाल यह भी ध्यान रखना होगा कि जुलाई में रिटर्न की मात्रा इसलिए भी बड़ी क्योंकि करदाताओं को 5-8 दिन अधिक समय दिया गया था, जो इसके लिए था कि वे जीएसटी के पहले के स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना चाहते हैं या नहीं। जीएसटीएन को उम्मीद है कि रिटर्न फाइलिंग जुलाई के बराबर पहुंच जाएगी।

अगर अगस्त महीने में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या जुलाई के बराबर रहती है तो यह अनुपातिक रूप से कम होगा। ऐसा इसलिए कि जुलाई में जीएसटी के तहत पंजीकरण सिर्फ 59.5 लाख थे, जिसमें वे लोग शामिल नहीं हैं, जिन्होंने कंपोजिशन योजना का विकल्प चुना था। अब करीब 90 लाख पंजीकरण हैं। इसमें से करीब 10 लाख कंपोजिशन योजना में हैं, जो तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जुलाई महीने में 95,000 करोड़ रुपये एकत्र हुए थे। केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी अधिनियम के मुताबिक कर के भुगतान में देरी पर 18 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना होगा। देरी से एसजीएसटी और सीजीएसटी दाखिल करने पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।

जीएसटीएन के चेयरमैन अजय भूषण पांडे ने कहा कि जीएसटी नेटवर्क काफी मजबूत स्थिति में है और अभी तक जितने रिटर्न दाखिल किए गए हैं उनसे पता चलता है कि नेटवर्क बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में समस्याएं या अड़चनें आ रही हैं उन्हें तेजी से हल किया जाएगा। पांडे ने कहा कि अभी तक अगस्त महीने के लिए कुल 29.41 लाख जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटीएन ने कल हर घंटे 85,000 रिटर्न स्वीकार किए। यह अगस्त के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन था। कल तक 75 प्रतिशत पंजीकृत इकाइयों ने अपने रिटर्न जमा नहीं कराए थे।

बीएस सूडोकू 2926 | परिणाम संख्या 2925

3			6		9	2		7
	9		1			3	4	
4	8	2				6		1
		4	2				7	
	6	9				4	5	
	1				8	9		
5		6				7	3	9
	7	3			6		1	
1		8	9		3			2

9	8	5	6	1	4	7	2	3
2	4	7	5	8	3	9	1	6
6	3	1	7	2	9	4	5	8
3	6	9	8	5	7	2	4	1
5	2	4	1	3	6	8	7	9
1	7	8	9	4	2	3	6	5
7	1	6	4	9	8	5	3	2
8	5	3	2	7	1	6	9	4
4	9	2	3	6	5	1	8	7

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम
★
★
★
☆
☆

ई-नाम में एमएसपी खरीद की अलग व्यवस्था का समर्थन

संजीब मुखर्जी
नई दिल्ली, 21 सितंबर

केंद्र सरकार मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के तहत खरीद के रिकॉर्ड के लिए अलग सेगमेंट बनाए जाने के पक्ष में है, जिससे इसे ऑनलाइन बोली से अलग किया जा सके।

हालांकि अधिकारियों ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से यह ई-नाम पोर्टल पर पहले से निर्धारित एमएसपी पर कृषिउत्पादों की बिक्री की पूरी व्यवस्था के विरुद्ध है,, क्योंकि इस व्यवस्था में खुली प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से प्राइस डिस्कवरी की अवधारणा पेश की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी तरह से उपेक्षा करना भी शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि यह किसानों को होने वाले भुगतान को लेकर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करता है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ राज्यों में ई-नाम के माध्यम से लेन देन में भारी बढ़ोतरी हुई, जब उन्होंने एमएसपी व्यवस्था के तहत हुई खरीद को इसमें दिखाना शुरू कर दिया। समीक्षा में पाया गया कि ई-नाम के तहत ज्यादातर लेन देन एकल बोली पर आधारित था।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली | पंजाब | हरियाणा

थोक भाव रुपये प्रति क्विंटल

दिल्ली

अनाज : गेहूं स.प. (देसी) 2,100-2,350 रुपये, गेहूं दड़ा (मिल्ल के लिए) 1,760-1,765 रुपये, चक्की आटा (डिलीवरी) 1,765-1,770 रुपये, आटा राजधानी (10 किग्रा) 260-300 रुपये, क्विंटलभोग (10 किग्रा) 250-290 रुपये, शेलर फ्लोर मिल्ल 950-960 रुपये, (50 किग्रा), मैदा 990-1,000 रुपये, (50 किग्रा) और सूजी 1,030-1,040 रुपये (50 किग्रा)। बासमती चावल (लालकिला) 10,700 रुपये, श्री लाल महल 11,300 रुपये, पूपर बासमती चावल 9,800 रुपये, बासमती ज्वेलिंग लई 6,900-6,900 रुपये, चावल पूसा (1121) 5,500-5,550 रुपये, परमल कच्चा 2,200-2,225 रुपये, परमल वेरड 2,250-2,275 रुपये, सेला 2,500-2,400 रुपये और सावल आईआर-3816 1,850-1,575 रुपये, चावल 1,180-1,150 रुपये, आर पीला 1,400-1,450 रुपये, रुपैर 2,800-2,900 रुपये, मक्का 1,250-1,295 रुपये, जौ 1,450-1,440 रुपये

दलहन : उड़द 4,800-6,100 रुपये, उड़द छिलका (रंगारेज) 5,700-5,800 रुपये, उड़द बेदरहीन 5,500-6,300 रुपये, चना 6,200-6,400 रुपये, मूंग 4,900-5,600 रुपये, दाल मूंग छिलका स्थानीय 5,600-5,800 रुपये, मूंग पीला स्थानीय 6,200-6,700 रुपये और देसीहल क्वालिटी 6,700-6,900 रुपये। मसूर छोटी 3,700-3,800 रुपये, बोल्ड 3,750-3,900 रुपये, दाल मसूर स्थानीय 3,900-4,400 रुपये, वेहतरीन गुणवत्ता 4,000-4,500 रुपये, लालका स्थानीय 4,450-4,650 रुपये, लालका वेहतरीन गुणवत्ता 4,550-4,750 रुपये, मोठ 3,600-4,000 रुपये, अरहर 4,150 रुपये, दाल अरहर पट्ट 6,300-6,200 रुपये। मोठ 6,100-6,550 रुपये, चना दाल स्थानीय 6,900-7,300 रुपये, वेहतरीन गुणवत्ता 7,200-7,400 रुपये, वेसन (35 किग्रा) हथियाराम 2,750 रुपये, राजधानी 2,750 रुपये, राजमा पिंजा 7,700-10,000 रुपये, छवुसी दाना छोले 9,800-11,000 रुपये

खन्ना

जीएसटी रहित (प्रति किग्रा): राइसवान (आधा)(प्रति पाइंड)100, राइसवान (आधाय) 99, खल सरसों 1720, डीओसी: राइसवान वेय लयेर 760, लाल 800, कैटीमसूअस 850, सरसों (दव) 14500, सूरजमुखी (दव) 13100/13200, अलाज: गेहूं 1740/1745, आटा (50 किलो)950, मैदा 1055, चोकर (49 किग्रा) 745 चोकर (30 किग्रा) 450

लुधियाना

दाल-दलहन: अरहर विना 9000/9500, अरहर दाल 5800/6500, उड़द साबुत 5500/6000, उड़द धोया 7000/8000, छिलका 6000/7000, दाल मसूर 4500/5100, चनादाल 7500/7600, चावली धवा 11000/13000, मूंग साबुत 5500/6000, मूंग धोया 6300/6800, चावल: डीवी 6100/6200, सरवती स्टीम 4200/4300,चावल 1121 सेला 5300/5400, लालकिला 12000, तेल: विनोला 6200, सरसों 7700, खल: सरसों 1745/1775, विनोला 2000/2100, डीओसी: मूंगफली 22400, सूरजमुखी 14000

अमृतसर

चावल: बासमती (1121 ने.) स्टीम 6400/6450, सेला 5600/5650, शरवती साधारण सेला, 3200/3300, शरवती स्टीम 4200/4300, धान: शरवती 1875/2000, बासमती 1121 धान 3200/3250, धान (1509) 2450/2600 पीआर 1750/1850, कुट (किग्रा): साडू मंगोली१×, देसी पंजाब 39/5, लाकार देसी 4300, पूरा खंड 4100/4200

बठिंडा

रुई (प्रति मन): जे-34 फाक्स नई 3890/3990, हरियाणा 3980/3985, राजस्थान 3965/3985, खल (प्रति क्विं.): विनोला 2000/2050, सरसों खल 1600, गेहूं चोकर (28 किलो) 425

करनाल

गेहूं दड़ा 1570/1590, बासमती चावल 5900/6700, धान 1121 ने. 3125/3150, पूसा 1509 धान नया 2350/2400, शरवती धान 1575/1650, सेला (1509 ने.) चावल नया 4750/4800, सेला 1121 चावल 5500/5550, स्टीम 6200/6300, शरवती चावल सेला 3400/3450, स्टीम 4300/4400, चावल परमल काच्चा 2350/2450, सेला 2200/2225, आईआर-(8) सेला 1950/1980, धान 6500/6500, चना दाल 7600/7700

हिसार

ज्वार 3575/3600, जौ 1350/1360, सरसों 3350/3400, बाजरा 1180/1190, गेहूं 1610/1615, बरसा कपास 4000/4100

आभार: एग्रीवाचर